नईदुनिया



# एम्स विजयपुर बना जम्मू-कश्मीर का मेडिकल गेमचेंजर

## गेट पर ही शुरू हो जाता है स्मार्ट इलाज

## पहाड़ी राज्यों के मरीजों के लिए वरदान

डॉ. शिशिर उपाध्याय, जम्मू एम्स

**जम्मू-विजयपुर, सांबा।** अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, एम्स विजयपुर अब सिर्फ एक अस्पताल नहीं, बल्कि पूरे उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों के लिए स्वास्थ्य का नया हब बन गया है। सबसे बड़ी बात सामने आई है यहां का पेशेंट फर्स्ट और टेक्नोलॉजी फर्स्ट मॉडल। एम्स विजयपुर के निदेशक प्रो. डॉ. संजीव सिन्हा ने बताया कि रोजाना 1000 से 2000 के बीच, औसतन 1500 मरीज यहां ओपीडी में आते हैं। इनमें 60 प्रतिशत मरीज जम्मू-कश्मीर के दूरदराज पहाड़ी जिलों डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, उधमपुर के होते हैं, जबकि 40 प्रतिशत मरीज पंजाब, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और यहां तक कि दिल्ली से भी रेफर होकर इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। पहले इन मरीजों को 600 किलोमीटर दूर दिल्ली एम्स जाना पड़ता था। अब 2 से 3 घंटे में विजयपुर में वर्ल्ड क्लास इलाज मिल रहा है।

### गेट से ही सक्रिय हो जाता है डिजिटल सिस्टम, कागज का झंझट खत्म

एम्स विजयपुर का सबसे बड़ा इनोवेशन है उसका स्मार्ट हॉस्पिटल नेविगेशन सिस्टम। मीडिया दल ने खुद इसका ट्रायल देखा।

**ऑनलाइन पंजीयन :** लाइन में लगने की जरूरत नहीं। गेट पर लगे कियोस्क पर आधार कार्ड स्कैन करते ही 30 सेकंड में ऑनलाइन पंजीयन हो जाता है।

**सभी दस्तावेजों की ऑटो स्कैनिंग :** पुरानी रिपोर्ट, प्रिस्क्रिप्शन, आयुष्मान कार्ड को कियोस्क पर रखते ही सिस्टम उसे स्कैन कर इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड में जोड़ देता है।

**इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गाइडेंस :** पंजीयन के तुरंत बाद मरीज को एक टोकन और एसएमएस मिलता है, जिसमें साफ लिखा होता है कि उसे किस फ्लोर पर, किस विंग में, किस डिपार्टमेंट के किस कमरे में जाना है। रास्ते में लगे इंटेलिजेंट पेशेंट नेविगेशन कियोस्क, जो हिंदी, अंग्रेजी और डोगरी तीन भाषाओं में बोलते हैं, मरीज को आवाज देकर गाइड करते हैं।

**तत्काल क्वेरी समाधान :** किसी भी जांच रिपोर्ट या डॉक्टर की उपलब्धता की क्वेरी के लिए हेल्पडेस्क पर भटकना नहीं पड़ता। कियोस्क पर क्वेरी टाइप करते ही तत्काल लोकेशन और समय की जानकारी मिल जाती है। इससे दलालों और बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह खत्म हो गई है।

### रिसर्च कैपिटल बन रहा है विजयपुर एम्स

रेडियोथेरेपी और ऑन्कोलॉजी विभाग के हेड और डीन रिसर्च प्रो. डॉ. शबाब ललित अंगुराना ने बताया कि एम्स विजयपुर सिर्फ इलाज नहीं, रिसर्च का भी बड़ा केंद्र बन रहा है।

**छात्रों के लिए 23 आईसीएमआर प्रोजेक्ट्स :** एमबीबीएस छात्रों में वैज्ञानिक जिज्ञासा बढ़ाने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सहयोग से 23 शॉर्ट-टर्म रिसर्च प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं।

**भविष्य की तैयारी :** जल्द ही यहां न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग और अत्याधुनिक पीईटी-सीटी स्कैन इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू होगा। इससे कैंसर की शुरुआती स्टेज में ही पहचान हो सकेगी और जम्मू में ही कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की पूरी सुविधा मिलेगी। मरीजों को अब 500 किमी दूर जाने की जरूरत नहीं होगी। एम्स विजयपुर ने साबित कर दिया है कि पहाड़ी राज्य में भी अगर इच्छाशक्ति हो तो दिल्ली जैसा विश्वस्तरीय, टेक्नोलॉजी-ड्रिवन और गरीब-हितैषी हेल्थ मॉडल खड़ा किया जा सकता है।

**12 हाई-इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स :** पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाले कैंसर, थायरॉइड और दिल की बीमारियों पर ऊर्जावान युवा फैकल्टी 12 बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है।

### 750 बेड, 30 ब्रॉड और 14 सुपर स्पेशलिटी, पहाड़ से मैदान तक सबका इलाज एक ही छत के नीचे

प्रो. डॉ. सिन्हा ने बताया कि संस्थान 750 बेड की क्षमता के साथ पूरी तरह फंक्शनल है। मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24×7 इमरजेंसी मेडिसिन ब्लॉक और इंटीग्रेटेड आयुष सेंटर है, जहां एलोपैथी के साथ-साथ आयुर्वेद और योग से भी इलाज होता है। कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी समेत 30 ब्रॉड स्पेशलिटी और 14 सुपर स्पेशलिटी विभाग यहां काम कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा पहाड़ी राज्यों के मरीजों को मिला है। हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, जलने और सड़क हादसों के गंभीर मरीजों को अब गोल्डन ऑवर में ही इलाज मिल रहा है। जरूरत पड़ने पर एम्स नई दिल्ली की स्पेशलाइज्ड टीम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और कई बार मौके पर आकर भी जटिल सर्जरी में मदद करती है। यह इस पूरे क्षेत्र का पहला अस्पताल है, जिसे एनएबीएच एक्रेडिटेशन, नागपुर का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अवॉर्ड और नेशनल पेशेंट सेफ्टी अवॉर्ड मिला है। जल्द ही यहां एडवांस्ड रोबोटिक सर्जरी सिस्टम भी शुरू होने वाला है, जिससे सर्जरी और सटीक होगी।

---

**73,480 पन्नों की चार्जशीट दाखिल, 67 कर्मचारियों के शामिल होने की आशंका**

# राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय सरकारी गवाह

**नईदुनिया ब्यूरो, अयोध्याः** अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ने फैजाबाद जिला न्यायालय में गुरुवार को 73,480 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट के अनुसार, काउंटिंग रूम में चढ़ावे की रकम छिपाते कर्मचारियों को एक कर्मचारी आनंद चौधरी ने देखा था। उसने तत्कालीन ट्रस्ट महासचिव चंपत राय को इसकी जानकारी दी और वीडियो भी भेजा था। वीडियो में कुछ कर्मचारी कमर में नोटों की गड्डियां छिपाते दिखाई दे रहे हैं। आनंद ने चोरी में करीब 67 कर्मचारियों के शामिल होने की आशंका जताई थी।

पूर्व ट्रस्ट महासचिव चंपत राय, डॉ. अनिल मिश्रा और गोपाल राव को आरोपी नहीं, बल्कि गवाह बनाया गया है। पुलिस ने मंदिर से कीमती आभूषण गायब होने की बात खारिज की है।

25 जून को मामला दर्ज कर रामशंकर यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष

यादव, करुणेश पांडेय, रमाशंकर मिश्रा, अविनाश शुक्ला और सेवानिवृत्त बैंककर्मी सुभाष श्रीवास्तव को आरोपी बनाया गया था।

4 जून को मामला सामने आने के बाद मंदिर परिसर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। जांच में चढ़ावा चोरी से जुड़ी 105 घटनाएं कैमरों में दर्ज मिलीं। पुलिस ने 173 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं। चार्जशीट में आठ आरोपियों के खिलाफ सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल से मिले डिजिटल साक्ष्य, गवाहों के बयान, बैंक खातों में नकद जमा, संपत्ति खरीद और बरामदगी से जुड़े साक्ष्य पेश किए गए हैं।

जांच के अनुसार, चढ़ावे की रकम की गिनती और छंटाई में लगे कर्मचारियों पर चोरी का आरोप है। पुलिस को कुछ आरोपियों के मोबाइल से नकदी रखने, छिपाने और इधर-उधर ले जाने से संबंधित संदेश मिलने का भी उल्लेख किया गया है। पुलिस के मुताबिक, अविनाश शुक्ला सीसीटीवी में 85 बार चढ़ावे की रकम हटाते और चार बार अन्य आरोपियों की मदद करते दिखाई दिया। उसकी निशानदेही पर 20.39 लाख रुपये, विदेशी मुद्रा, सोने-चांदी के आभूषण और कार बरामद करने का दावा किया गया है। लवकुश मिश्रा पर चोरी की रकम से जमीन और मकान खरीदने का आरोप है।

चार्जशीट में करुणेश पांडेय के परिवार के खातों में नकद जमा, रमाशंकर मिश्रा के परिवार के खातों में 20.93 लाख रुपये जमा होने और रमाशंकर यादव के खातों में 8.48 लाख रुपये जमा होने का भी उल्लेख है।

# एआई ने सरकारी हेल्थ डेटा सिस्टम में लगाई सेंध, 54 दिन बाद दी जानकारी

**ओपनएआई मॉडल ने स्वास्थ्य खर्च और दवा सब्सिडी से जुड़ी फाइलों तक पहुंच बनाई, सैम ऑल्टमैन ने वैश्विक सुरक्षा मानकों की जरूरत बताई**

**कैनबरा, एजेंसीः** ऑस्ट्रेलिया में एक एआई मॉडल के सरकारी हेल्थ डेटा सिस्टम में घुसने की घटना सामने आई है। ओपनएआई के मॉडल ने सिस्टम की फाइलों तक पहुंच बनाकर जानकारी हासिल की। इनमें स्वास्थ्य खर्च और दवा सब्सिडी से जुड़ा डेटा शामिल था। ओपनएआई ने घटना की जानकारी ऑस्ट्रेलियाई सरकार को 54 दिन बाद दी।

मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने न्यूयॉर्क में ओपनएआई के प्रमुख सैम ऑल्टमैन से फोन पर बात की और जानकारी देने में हुई देरी पर नाराजगी जताई। ऑल्टमैन ने कहा कि एआई पर मानवीय नियंत्रण बनाए रखना जरूरी हो गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इंसानी नियंत्रण खो गया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

ऑस्ट्रेलिया अब इस मामले की जांच करेगा। जांच में यह भी देखा जाएगा कि कंपनी के खिलाफ आपराधिक मामला बनता है या नहीं। इसके अलावा यह पता लगाया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा एजेंसियां एआई मॉडल की इस घुसपैठ को पहले क्यों नहीं पकड़ सकीं।

ओपनएआई ने भी माना है कि उसके मॉडल ने ऐसे कदम उठाए, जिनका कंपनी ने इरादा नहीं किया था। ऑल्टमैन ने कहा कि दुनिया के देशों को मिलकर एआई के लिए सुरक्षा मानक तय करने की जरूरत है, ताकि तकनीक के अधिक शक्तिशाली होने के बावजूद उस पर नियंत्रण बना रहे।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी एआई से जुड़े संभावित खतरों पर चर्चा हुई। एंथ्रोपिक के प्रमुख अमोडेई ने कहा कि गलत तरीके से संभाला गया एआई मानवता के लिए खतरा बन सकता है। उन्होंने जैविक हथियारों के निर्माण में एआई के इस्तेमाल को रोकने के लिए साझा नियमों की जरूरत बताई।

हगिंग फेस के प्रमुख क्लेमेंट डेलांग ने एआई की क्षमता को किसी एक कंपनी या देश तक सीमित नहीं रखने पर जोर दिया।

इस बीच, एंथ्रोपिक के एआई मॉडल क्लॉड ने डीएनए डेटा का विश्लेषण कर एआरटी नाम का एंजाइम सिस्टम खोजा है। करीब 950 एआई एजेंट्स ने दो लाख से अधिक एंजाइम का विश्लेषण कर इसे 21 घंटे में खोजा। इससे जीन शोध में नए रास्ते खुलने की संभावना बताई गई है।

# ईरान की चेतावनी- हमारे विमान रोके तो क्षेत्र में किसी देश का विमान नहीं उड़ने देंगे

**तेहरान, एजेंसीः** ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि दूसरे देशों ने अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत उसके विमानों को रोकने या एयरपोर्ट सुविधाएं देने से इनकार किया, तो वह भी क्षेत्र में हवाई सेवाओं को रोक सकता है। ईरान के सर्वोच्च नेता के सलाहकार मोहम्मद मुखबर ने कहा कि अगर ईरानी विमान उड़ान नहीं भर सकते तो क्षेत्र के किसी अन्य देश का विमान भी नहीं उड़ सकेगा।

ईरान से हर दिन करीब 100 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित होती हैं। हालांकि, अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, अजरबैजान, जॉर्जिया और इराक समेत कई जगहों पर ईरानी उड़ानों को रोका गया है। इसके चलते ईरान की अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाओं पर असर पड़ा है।

अमेरिका ने ईरान की सभी एयरलाइंस को बंद कराने की चेतावनी दी है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि यदि कोई देश या कंपनी ईरानी विमानों को ईंधन या उतरने की सुविधा उपलब्ध कराती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

अमेरिका ने सितंबर में ईरान के विमानन क्षेत्र पर प्रतिबंधों का दायरा और बढ़ाया। 8 सितंबर को अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने ईरान की बची हुई 27 एयरलाइंस को भी प्रतिबंधों के दायरे में शामिल कर लिया। इसके अलावा उन विदेशी कंपनियों पर भी कार्रवाई की गई, जिन पर ईरानी एयरलाइंस को विमान, सामान या अन्य विमानन सेवाएं उपलब्ध कराने का आरोप है। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरानी एयरलाइंस की अंतरराष्ट्रीय सेवाओं को प्रभावित करना है। इन सेवाओं के संचालन के लिए ईरानी विमानन कंपनियां दूसरे देशों के एयरपोर्ट और विमानन सुविधाओं पर निर्भर रहती हैं। ऐसे में एयरपोर्ट पर उतरने, ईंधन लेने और अन्य विमानन सेवाएं मिलने में रोक से उनकी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर असर पड़ सकता है। ईरान की ओर से दी गई चेतावनी ऐसे समय आई है, जब अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद कई देशों में ईरानी उड़ानों को लेकर प्रतिबंधात्मक कदम उठाए गए हैं।

### मणिपुर, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश में सुरक्षा बल तैनात रहेंगे

**नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली:** केंद्र सरकार ने मणिपुर, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, 1958 की अवधि छह महीने के लिए बढ़ा दी है। यह अवधि 1 अक्टूबर से लागू होगी। सरकार ने संबंधित क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया है। मणिपुर में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पांच जिलों के 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाकों को छोड़कर पूरे राज्य में अशांत क्षेत्र की घोषणा को छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। इन इलाकों में एएफएसपीए लागू रहेगा। वहीं, जिन क्षेत्रों को इस आदेश से बाहर रखा गया है, वहां यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। नगालैंड में एएफएसपीए की अवधि नौ जिलों में बढ़ाई गई है। इनमें दीमापुर, निउलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफायर, नोकलाक, फेक, पेरेन और मेलुरी जिले शामिल हैं। इन जिलों में 1 अक्टूबर से अगले छह महीने तक अधिनियम प्रभावी रहेगा।

---

**पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल पर जयशंकर का जवाब**

# एक आतंकी देश मुझसे यह सवाल पूछ रहा है

**न्यूयॉर्क, एजेंसीः** विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान एक पाकिस्तानी पत्रकार के आतंकवाद से जुड़े सवाल पर जवाब दिया। पत्रकार ने पूछा कि दक्षिण एशिया नई दिल्ली, काबुल और इस्लामाबाद से फैलने वाले आतंकवाद का सामना कब तक करता रहेगा। इस पर जयशंकर ने कहा, 'एक आतंकवादी देश मुझसे यह सवाल पूछ रहा है।' इसके बाद उन्होंने सवाल का जवाब दिया और वहां से चले गए। घटना संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत की विदेश नीति, वैश्विक सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय प्रयासों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। जयशंकर ने खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में व्यापारिक जहाजों पर बढ़ते हमलों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि समुद्री मार्गों पर होने वाले ऐसे हमले अब कभी-कभार होने वाली घटनाएं नहीं रह गए हैं। इससे वैश्विक व्यापार और नाविकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है।

जयशंकर ने लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेयसोलो नयंती के साथ जहाजों और नाविकों की सुरक्षा से जुड़े 'ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स' की बैठक में भी समुद्री सुरक्षा का मुद्दा उठाया। पिछले तीन महीनों में समुद्री जहाजों पर हुए हमलों में भारतीय नाविकों के प्रभावित होने के मामले सामने आए हैं। 8 जुलाई को काला सागर में एमवी ओमोर्फी पर हमले में एक भारतीय मुख्य अधिकारी की मौत हुई। 19 जुलाई को एमवी गोल्डन लियो पर हमले में चार भारतीय नाविकों की मौत हुई। 9 सितंबर को होर्मुज जलडमरूमध्य में एल गैया टैंकर पर हमले के बाद एक भारतीय चालक दल का सदस्य लापता हुआ। 17 सितंबर को ओमान की खाड़ी में एमवी केप डाओ पर हमले में एक भारतीय नाविक की मौत हुई। जयशंकर ने समुद्री मार्गों की सुरक्षा और नाविकों की सुरक्षा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण मुद्दा बताया।

## जमुई पीड़िता की तस्वीर को लेकर विवाद

### मुख्यमंत्री पर एफआईआर की मांग

**नईदुनिया ब्यूरो, पटनाः** बिहार के जमुई में नाबालिग से बदसलूकी के मामले में पीड़ित परिवार की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा किए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पीड़ित परिवार ने गुरुवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री के आधिकारिक एक्स हैंडल से परिवार के साथ तस्वीर साझा की गई। तस्वीर कुछ समय बाद हटा दी गई। इसके बाद राजद सांसद मीसा भारती ने मुख्यमंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की है। पीड़ित बच्ची की मां ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद कहा कि घटना का दर्द अब भी है, लेकिन कार्रवाई और सुरक्षा को लेकर मिले आश्वासन से राहत मिली है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी के साथ जो हुआ, वह दोबारा किसी दूसरी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। उन्होंने आरोपितों के भीतर कानून का डर होने की भी मांग की। मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल से साझा की गई पोस्ट में पीड़ित बच्ची और उसके परिवार से मुलाकात का उल्लेख किया गया था। पोस्ट में परिवार को शीघ्र न्याय का भरोसा देने और सभी आरोपितों के खिलाफ तेजी से सुनवाई के माध्यम से एक महीने के भीतर कड़ी सजा सुनिश्चित करने की बात कही गई थी। तस्वीर बाद में हटा दी गई। तस्वीर सामने आने के बाद बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा।

**पहल** *पहले लड़ाई रुके, सातवें दिन होर्मुज खोलने पर होगी बात...*

# ईरान ने अमेरिका के सामने रखा 7 दिन में युद्ध रोकने का प्रस्ताव

**न्यूयॉर्क, एजेंसीः** ईरान ने अमेरिका के सामने युद्ध रोकने के लिए सात दिन का प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव के अनुसार, सबसे पहले सभी मोर्चों पर लड़ाई रोकी जाए और ईरान के तेल निर्यात पर लगे प्रतिबंधों में राहत दी जाए। इसके बाद सातवें दिन होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने पर बातचीत होगी और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर नई वार्ता शुरू की जाएगी। यह प्रस्ताव ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने मध्यस्थ देशों के माध्यम से अमेरिका को भेजा है।

ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजशकियान ने कहा कि अब अमेरिका को तय करना है कि वह संघर्ष खत्म करना चाहता है या नहीं। उन्होंने कहा कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए अमेरिकी हमले रुकना जरूरी है। पजशकियान ने एक साक्षात्कार में कहा कि जून में अमेरिका और ईरान के बीच एक समझौते का आधार तैयार हो गया था और ईरान आगे बढ़ने के लिए तैयार था। उनके अनुसार, उस समय होर्मुज जलडमरूमध्य खुला था और बातचीत का रास्ता भी खुला था, लेकिन इसके बाद अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया।

ईरान का यह प्रस्ताव उस समय आया है जब दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पजशकियान ने कहा था कि ईरान अमेरिकी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि समझौता नहीं होने पर अमेरिका ईरान को पूरी तरह तबाह कर सकता है। 8 सितंबर को अमेरिकी सेना ने ईरान से जुड़े पांच तेल टैंकरों पर हमला किया था। इसके बाद ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकाने की ओर 20 बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। जॉर्डन के अनुसार, उसके वायु रक्षा तंत्र ने 18 मिसाइलों को मार गिराया। इसके बाद ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य में 10 जहाजों पर हमले की बात कही थी। इनमें दो अमेरिकी जहाज और आठ तेल टैंकर शामिल थे। ईरान ने एक अमेरिकी पनडुब्बी ड्रोन पकड़ने की भी जानकारी दी थी।

अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू की थी। अमेरिका का कहना है कि उसका उद्देश्य ईरान की परमाणु क्षमता को कमजोर करना है। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और उसे परमाणु तकनीक के इस्तेमाल का अधिकार है।